(मंजरी नेहरू कौल, जे.)

राजन गुप्ता और मंजरी नेहरू कौल, जे. जे.के सम्मुख

अशोक कौशिक-अपीलार्थी

बनाम

सुनीता कौशिक उत्तरदाता (ओं)

एफएओ-एम-161-2015

29 अक्टूबर, 2019

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955-धारा 13-करूता के आधार पर पति की तलाक याचिका-निचली अदालत द्वारा खारिज-पति के साथ रहने वाला बेटा-लगभग 14 वर्षों तक वैवाहिक संबंध की अनुपस्थिति-संबंधों में खटास-पत्नी की पुलिस में शिकायत की पति ने उसे आग लगाने की कोशिश की, झूठी पाई गई-उसने यह भी आरोप लगाया कि पति के बिना किसी सबूत के दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध थे-अभिलेख और अदालत की पक्षों के साथ बातचीत से स्पष्ट हो गया कि उनके लिए एक साथ रहना असंभव था-आयोजित, विवाह को समाप्त करने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी-पत्नी को स्थायी गुजारा भत्ता के भुगतान के अधीन दिया गया।

ऐसा मानते हुए, पति ने आरोप लगाया है कि यह पत्नी के भाई और माता-पिता थे, जिन्होंने सुबह तड़के घर में प्रवेश करने के बाद उसे पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि पत्नी ने आरोप लगाया कि पति ने उसे आग लगाने की कोशिश की थी।यह भी बात है कि शिकायत झूठी पाई गई थी।इसमें कोई संदेह नहीं है कि पत्नी ने आरोप लगाया है कि यह सब पुलिस की मिलीभगत से किया गया था, हालांकि, तथ्य यह है कि दोनों पक्षों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं रहे हैं।पति के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करना उस स्थिति को दर्शाता है जिस स्थिति में पति-पत्नी के बीच संबंध आए हैं।उसने यह भी आरोप लगाया है कि पति के किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध हैं और उसने महिला के लिए एक घर भी खरीदा है।हालाँकि, ये आरोप केवल कागजों पर हैं जिनका समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है।

(पैरा 11) अभिलेख पर साक्षय के अवलोकन के साथ-साथ पक्षों के साथ हमारी बातचीत के बाद, कोई भी यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि दोनों पक्षों के अपने वैवाहिक जीवन को जारी रखने के लिए एक साथ रहने की कोई उम्मीद नहीं है ।मान लीजिए, पिछले कम से कम 13 से 14 वर्षों से दोनों पक्षों के बीच वैवाहिक संबंध का अभाव रहा है।

इस मामले में, हमें यह निष्कर्ष निकालने में कोई संकोच नहीं है कि पक्षों के बीच विवाह केवल कागजों पर मौजूद है और मरम्मत से परे टूट गया है।

(पैरा 13)

गौतम दत्त, अधिवक्ता

अपीलार्थी के लिए।

राजिंदर गोयल, प्रतिवादी (ओं) के वकील।

मंजरी नेहरू कौल, जे.

(1) एल. डी. द्वारा पारित 11 फरवरी, 2015 के फैसले और डिक्री को चुनौती देते हुए पति-अशोक कौशिक द्वारा तत्काल अपील की गई है। एडल्ट।जिला न्यायाधीश, चंडीगढ़ (इसके बाद 'एल. डी.' के रूप में संदर्भित)। '), जिसके माध्यम से हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 (इसके बाद' अधिनियम 'के रूप में संदर्भित) के तहत प्रतिवादी-पत्नी/सुनीता कौशिक के साथ अपनी शादी को भंग करने के लिए उनके द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया गया था।

(2) तत्काल अपील के निर्णय के लिए आवश्यक कुछ तथ्य, जैसा कि अपीलार्थी-पति (उसमें याचिकाकर्ता) द्वारा एल. डी. के समक्ष दायर याचिका में कहा गया है। नीचे दिए गए न्यायालय पर ध्यान दिया जा सकता है।

(3) दोनों पक्षों के बीच शादी 29 नवंबर, 1991 को चंडीगढ़ में हिंदू संस्कारों और अनुष्ठानों के अनुसार संपन्न हुई थी।उक्त विवाह से 6 अगस्त, 1993 को एक बेटे का जन्म हुआ।प्रत्यर्थी-पत्नी का व्यवहार असामान्य लग रहा था और इसलिए, अपीलार्थी-पति ने उससे किसी भी मानसिक असामान्यता के लिए खुद की चिकित्सकीय जांच कराने का अनुरोध किया, लेकिन उसने किसी भी चिकित्सा परीक्षण से गुजरने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया।नवंबर, 1994 में, उन्होंने अपने 15 महीने के बेटे को भी छोड़कर अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया।उसने एक बार भी बच्चे से मिलने की जहमत नहीं उठाई।इसके बाद बच्चे का पालन-पोषण पति और उसके परिवार ने किया।पति द्वारा उसे वैवाहिक घर वापस लाने के लिए किए गए गंभीर और बार-बार प्रयासों के बावजूद, उसने उसकी कंपनी में शामिल होने से इनकार कर दिया।अलग होने की इस अवधि के दौरान, पत्नी के पिता ने चंडीगढ़ में 21 फरवरी, 1997 को डी. डी. आर. संख्या 21 के माध्यम से पति के खिलाफ झूठे आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई।मामला तभी सुलझा जब पति ने लिखित रूप में बताया कि वह फिर से उसके घर नहीं जाएगा।जब पति जून, 2009 में पंचकूला में अपने घर चला गया, तो पत्नी के भाई ने उसे वैवाहिक घर के द्वार पर छोड़ दिया।पति ने उसे वापस स्वीकार कर लिया और उसे घर की

पहली मंजिल पर सभी सुविधाएं प्रदान कीं, जिसमें एक अशोक कौशिक बनाम सुनीता कौशिक भी शामिल थी।

833 अशोक कौशिक बनाम सुनीता कौशिक

(मंजरी नेहरू कौल, जे.)

जिसमें स्वतंत्र रसोई और अन्य नियमित खर्च के साथ अपने बेटे और पति के साथ पत्नी अलग रहती थी और उसके परिवार के साथ बातचीत नहीं करती थी 06 नवंबर, 2011 को पत्नी के माता-पिता और भाई लगभग 4:30 बजे सायःघर में घुसे और उसके साथ शारीरिक हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप पति को कई चोटें आईं।जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पत्नी ने इसके बजाय शिकायत दर्ज कराई कि पति ने जबरन उसके कमरे में घुसकर उसे आग लगाने की कोशिश की

थी।बाद में इन आरोपों को झूठा पाया गया।इसके अलावा, उसने आरोप लगाया कि पति के किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध थे और पति के अवैध संबंध से महिला को एक बच्चा भी पैदा हुआ था।

(4) इसके विपरीत, प्रत्यर्थी-पत्नी (उसमें प्रत्यर्थी) ने एल.डी. के समक्ष दायर अपने लिखित बयान में पति के आरोपों का स्पष्ट रूप से खंडन और खंडन किया। नीचे अदालत।उसने प्रस्तुत किया कि 05 नवंबर, 2011 को, वह अपनी जान बचाने के लिए अपना वैवाहिक घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गई थी, क्योंकि पति और उसके परिवार ने उसे आग लगाने की कोशिश की थी।उसने आरोप लगाया कि अधिनियम की धारा 13 के तहत अपीलार्थी-पति द्वारा दायर याचिका उसके पति के खिलाफ धारा 159 (3) Cr.P.C के तहत 25 नवंबर, 2011 को उसके द्वारा दायर शिकायत के खिलाफ थी।उसने इस बात से इनकार किया कि वह किसी भी मानसिक असामान्यता से पीड़ित थी।बल्कि, उसने आरोप लगाया कि यह पति और उसका परिवार था, जो उसे लगातार क्रूर और कठोर व्यवहार के अधीन कर रहे थे।वह अपनी शादी को बचाने के लिए ऐसा ही सहन कर रही थी।उसने आगे आरोप लगाया कि पति और उसका परिवार लालची था।बहुत पहले 1991 में, पार्टियों की शादी से पहले, दिवाली के अवसर पर, उनके ससुर द्वारा एक कार और अन्य वस्तुओं की मांग की गई थी।जब उसके माता-पिता ने शादी रद्द करने की इच्छा व्यक्त की थी, तो उसके सास-ससुर ने माफी मांग ली थी और मामले को सुलझा लिया था।उसने दावा किया कि उसके माता-पिता ने उसकी शादी पर बड़ी राशि खर्च की थी।उसे उसके बेटे के जन्म की नियत तारीख से कुछ महीने पहले उसके माता-पिता के घर भेज दिया गया था और प्रसव के समय सभी खर्च उसके माता-पिता द्वारा वहन किए गए थे।उसने कहा कि पति धमकी देगा कि वह उसके एक डॉक्टर दोस्त से उसे गलत असामान्यता प्रमाण पत्र दिलाएगा और फिर उसे वैवाहिक घर से बाहर निकाल देगा।उसने आरोप लगाया कि जब वह पंचकुला में पति के नए घर में उसके साथ शामिल हुई, तो उसके बेटे को उसकी पिटाई करने के लिए उकसाया गया।पति ने उसे बताया कि जब तक वह अपने पिता की संपत्ति से अपना हिस्सा नहीं लेती, तब तक वह उसे प्रताड़ित करता रहेगा।05 नवंबर, 2011 को लगभग 11:30 बजे रात में, उसका पति नशे की हालत में जबरन उसके कमरे में घुस गया और उसे आग लगाने की कोशिश की, लेकिन वह समय पर भागने में सफल रही।वह पुलिस और अपने भाइयों को बुलाने के लिए मजबूर हुई।

मदद के लिए।डी. डी. आर. पंजीकृत किया गया।हालांकि, पति के उच्च संबंधों के कारण कभी कोई मामला दर्ज नहीं हुआ।उसने दलील दी कि उसने न तो किसी भी तरह से पति को कोई शारीरिक और मानसिक पीड़ा दी है और न ही उसने उसे छोड़ दिया है, जैसा कि अपीलार्थी-पति द्वारा दायर अधिनियम की धारा 13 के तहत याचिका में आरोप लगाया गया है।(5) इसके जवाब में, पति ने एक प्रतिकृति दायर की, जिसमें उन्होंने प्रतिवादी-पत्नी की दलीलों का विरोध किया और याचिका में लिए गए अपने रुख को दोहराया।

(6) पक्षकारों की दलीलों से, एल. डी. द्वारा निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए गए थे। न्यायालय नीचे:-

"1. क्या प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता के साथ क्रूरता का व्यवहार किया है? ओपीपी।

2. क्या प्रतिवादी ने बिना किसी उचित कारण के तलाक के लिए याचिका दायर करते समय याचिकाकर्ता को दो साल से अधिक की निरंतर अवधि के लिए छोड़ दिया है?ओपीपी "

(7) दोनों पक्षों ने एल. डी. के समक्ष अपने-अपने मामलों के समर्थन में साक्षय प्रस्तुत किए। नीचे अदालत।पति ने खुद को पीडब्लू-3 के रूप में जाँच किया, इसके अलावा, तीन अन्य गवाहों से जाँच की और उसके बाद, उसने अपना सबूत बंद कर दिया।दूसरी ओर, पत्नी ने खुद आर. डब्ल्यू.-1 के रूप में गवाह-पेटी में कदम रखा और अपने साक्षय को बंद कर दिया।

(8) साक्षय के साथ-साथ अभिलेख पर सामग्री का विश्लेषण करने के बाद, एल. डी. निचली अदालत ने पति द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।(9) हमने अपीलार्थी के विद्वान वकील को सुना है और अभिलेख पर साक्षय और अन्य सामग्री का पुनर्मूल्यांकन किया है।

(10) तत्काल अपील के लंबित रहने के दौरान, पक्षों को इस न्यायालय के मध्यस्थता और सुलह केंद्र को भेजा गया था, लेकिन यह व्यर्थ की कवायद साबित हुई।इस न्यायालय ने विभिन्न तिथियों पर पक्षों के साथ बातचीत भी की, लेकिन उनके बीच अत्यधिक कड़वाहट बहुत स्पष्ट थी क्योंकि दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ अपने आरोपों को दोहराया।(11) यह रिकॉर्ड की बात है कि 1997 में, पत्नी के पिता द्वारा पति के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके कारण पति ने लिखित रूप में दिया कि वह फिर से उसके घर नहीं जाएगा।यह बहुत स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के बीच संबंध कम से कम 1997 में खराब हो गए थे।इसके बाद, जब वह जून, 2009 में अपीलार्थी-पति के घर वापस चली गई, तो पति-पत्नी के बीच संबंध तनावपूर्ण बने रहे, जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट होगा

वह एक ही घर की पहली मंजिल पर रहती थी जबकि पति और बेटा निचली मंजिल पर रहते थे।निस्संदेह, 6 नवंबर, 2011 को पार्टियों के घर में कुछ घटना हुई थी। हालाँकि दोनों पक्षों ने इसके विपरीत बयान दिए हैं।पति ने आरोप लगाया है कि यह पत्नी के भाई और माता-पिता थे, जिन्होंने सुबह घर में प्रवेश करने के बाद उसकी पिटाई की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि पत्नी ने आरोप लगाया कि पति ने उसे आग लगाने की कोशिश की थी।यह भी रिकॉर्ड की बात है कि शिकायत झूठी पाई गई थी।इसमें कोई संदेह नहीं है कि पत्नी ने आरोप लगाया है कि यह सब पुलिस की मिलीभगत से किया गया था, हालांकि, तथ्य यह है कि दोनों पक्षों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं रहे हैं।पति के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करना उस स्थिति को दर्शाता है जिस स्थिति में पति-पत्नी के बीच संबंध आए हैं।उसने यह भी आरोप लगाया है कि पति के किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध हैं और उसने महिला के लिए एक घर भी खरीदा है।हालाँकि, ये आरोप केवल कागजों पर हैं जिनका समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है।

(12) यहाँ यह देखा जा सकता है कि पक्षों के साथ हमारी बातचीत के दौरान, पति ने कहा कि पक्षों के बीच संबंध इस हद तक बिगड़ गए थे कि पति-पत्नी के रूप में

एक साथ रहना असंभव था।हालाँकि, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि तत्काल अपील की अनुमति दिए जाने की स्थिति में, वह एक लाख रुपये की सीमा तक उचित राशि का भुगतान करने के लिए तैयार हैं। पत्नी को पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में 1 लाख रुपये।

(13) अभिलेख पर साक्षय के अवलोकन के साथ-साथ पक्षों के साथ हमारी बातचीत के बाद, कोई भी यह अनुमान लगा सकता है कि दोनों पक्षों के अपने वैवाहिक जीवन को जारी रखने के लिए एक साथ रहने की कोई उम्मीद नहीं है। मान लीजिए, पिछले कम से कम 13 से 14 वर्षों से दोनों पक्षों के बीच किसी भी वैवाहिक संबंध का अभाव रहा है।मामले के समग्र परिप्रेक्षय को लेते हुए, हमें यह निष्कर्ष निकालने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि पक्षों के बीच विवाह केवल कागजों पर मौजूद है और मरम्मत से परे टूट गया है।

(14) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम इस प्रकार एल. डी. द्वारा पारित 11 फरवरी, 2015 के विवादित निर्णय और डिक्री को दरकिनार कर देते हैं। नीचे अदालत।पक्षकारसभक बीच विवाह एतद्द्वारा तलाकक फरमान द्वारा भंग कऽ देल जायत छैक।तदनुसार डिक्री-शीट तैयार की जाए।हम अपीलार्थी-पति को रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश देते हैं। इस आदेश के पारित होने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए प्रतिवादी-पत्नी को स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में 80.00 लाख।यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि अपीलार्थी-पति उपरोक्त 836 का भुगतान करने में विफल रहता है

निर्धारित अवधि के भीतर प्रत्यर्थी-पत्नी को स्थायी गुजारा भत्ता की राशि, वर्तमान आदेश का कोई लाभ नहीं होगा और तत्काल अपील खारिज हो जाएगी, क्योंकि ऊपर बताए गए अनुसार अपील की स्वीकृति, अन्य बातों के साथ-साथ स्थायी गुजारा भत्ता के भुगतान पर आधारित है।

अंजना रानी

स्पष्टीकरणः– स्थानीय भाषा मे अनुवादित निर्णय वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा मे इसे समझ सके किसी अन्य उददेष्य के लिए इसका उपयोग नही किया जा सकता हे। सभी व्यवहारिक और अधिकारीक उददेष्यो के लए निर्णय का अग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कायान्वयन के उददेष्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।